अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–233 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ शुक्रवार 22 दिसम्बर 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

अकबरनगर पहुँचा बुलडोजर, पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, लाठीचार्ज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज गुरुवार को कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध रुप से बनाए गए अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 को ध्वस्त करने एलडीए की टीम भारी पुलिस बल लेकर पहुंची।लोगो ने विरोध किया । इस दौरान बीजेपी के महानगर मंत्री मंगल झा ने भी लोगों के साथ विरोध किया । पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। लोगो को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया जिसके चलते बंधा रोड, फैजाबाद रोड, महानगर रोड पर लंबा जाम लग गया। कॉलोनी वासियों ने हाईकोर्ट में कार्रवाई रोकने को लेकर अपील की। इसी के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के चलते कुछ देर के लिए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोकी गई। इलाके में एलडीए की टीम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोककर सुनवाई होने तक मकान व दुकान खाली कराना शुरु किया। अकबरनगर कुकरैल नदी की जमीन पर बना है। कुछ हिस्सा ग्रीन बेल्ट पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साबरमती की तर्ज पर लखनऊ में कुकरैल रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है। इसके बाद अकबरनगर पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया गया। लोगो ने इस फैसले का विरोध किया। गुरुवार को लोगो ने फिर एलडीए का विरोध किया। इस प्रदर्शन में एक भाजपा नेता भी शामिल था जिसका नोंकझोंक और धक्का मुक्की के बीच सिर फट गया। पुलिस ने उसे दौड़ा कर पकड़ा। कारवाई फिलहाल के लिए रोकी गई है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद फैसले का इंतजार है।

अवैध कब्जे का ध्वस्तीकरण करने पहुंची पुलिस की लोगों से झड़प, भाजपा महानगर मंत्री स्थानीय लोगों के समर्थन में उतरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में कुकरैल नाले के किनारे अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर– बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। नाराज स्थानीय लोगों ने कुकरैल बंधा रोड पर जाम लगा दिया जिससे अयोध्या रोड और महानगर रोड पर भीषण जाम लग गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के समर्थन भाजपा के महानगर मंत्री मंगल झा भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। जिस पर पुलिस ने उन पर भी हल्का बल प्रयोग किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मानें तो करीब 2700 मकान अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। जिसकी आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची है।

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्याएं, बोले-किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को

चेतावनी दी है कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। गोरखनाथ मंदिर में जनता जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान योगी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर कर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाए। मिली जानकारी के मुताबिक, मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। कुछ प्रकरणों पर उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि यह भी पता लगाएं कि यदि किसी को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ। हर पीड़ित की तुरंत मदद की जाए। आपको बता दें कि उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी।

राज्यपाल ने जनपद चित्रकूट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनपद चित्रकूट के कलेक्ट्रेट सभागार में केन्द्र सरकार द्वारा पोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। राज्यपाल ने

समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व शहरी, मनरेगा योजना, अमृत सरोवर निर्माण, खेल मैदान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य वित्त आयोग, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना, स्वच्छ शौचालय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक कैसे पहुंचे, इस पर सभी संबंधित अधिकारियों को सोचना चाहिए तभी गरीबों को लाभ मिलेगा। राज्यपाल जी ने निर्देश दिया कि जिन कार्यों के लिए शासन से धनराशि मिलती है। उसका समय से सदुपयोग करें। प्रत्येक कार्य का लक्ष्य तय करें और योजना बनाकर कार्य करें। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से कहा कि चित्रकूट की पावन धरा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो तीर्थ यात्री वहां पर दर्शन हेतु जाएंगे, वे चित्रकूट अवश्य आएंगे। इसलिए परिक्रमा पथ तथा तीर्थ क्षेत्र की साफ–सफाई नियमित रूप से की जाय। राज्यपाल ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि 3 वर्ष तक के सभी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में शत–प्रतिशत आने चाहिए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिया कि कोई भी परिवार अगर अन्य जनपद या बाहर किसी गांव में काम के लिए जा रहा है तो शिक्षकों को निर्देश दें कि वहां के विद्यालयों के अध्यापकों से संपर्क स्थापित कर वहां पर जो परिवार के बच्चे आपके विद्यालय में नामांकित है उनको वहां पर नामांकित कराकर शिक्षा ग्रहण अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विषय नहीं जिसका हल नहीं निकल सकता कार्य करने की मंशा सही होना चाहिए।राज्यपाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करें साथ ही यह भी प्रयास करें कि शत–प्रतिशत प्रसव शासकीय अस्पताल पर हो। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत अच्छी योजना है इसका सभी को लाभ दिया जाए टीबी रोगियों को गोद लेकर उनको पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाय। इस कार्य में व्यापार मंडल तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने राज्यपाल को एक जनपद एक उत्पाद के तहत स्मृति चिन्ह भेंट किया। बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

काशी तमिल संगमम–2 में शामिल होने तीसरा दल पहुंचा वाराणसी

वाराणसी। काशी तमिल संगमम–2 में शामिल होने के लिए तमिल श्रद्धालुओं का तीसरा दल गोदावरी गुरुवार को काशी पहुंचा। काशी–तमिल संगमम–2 के लिए विशेष ट्रेन से तमिल प्रोफेशनल ग्रुप का जत्था बनारस स्टेशन पहुंचा। बनारस की धरती पर उतरते ही दक्षिण भारतीय मेहमानों का 'वणक्कम काशी' कहके अभिवादन किया गया। ढोल–नगाड़े की थाप के बीच स्वस्तिवाचन और फूलों की वर्षा से शहर बनारस ने अपने अतिथि देवो भव के भाव से भी परिचित करायाकाशी तमिल संगमम–2 में शामिल होने पहुंचे तीसरा दल में प्रोफेशनल लोग है। काशी पहुंचे सभी डेलिगेट्स को धर्म, सभ्यता, इतिहास के बारे में बताया जायेगा। दूसरा एकेडमिक सत्र 22 दिसंबर को होगा। इसमें तमिलनाडु के प्रोफेशनल डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। इस एकेडमिक सत्र में भारतीय पेशेवरों के लिए चुनौतियां और अवसरों पर संवाद स्थापित किया जाएगा। इसमें आर्किटेक्ट अनिल किंजड़वेकर मुख्य अतिथि और वक्ता होंगे। काशी पहुंचे मेहमानों के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस यात्रा में मेहमानों को तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों की कला संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इसके आलावा प्रोफेशनल दल काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर, सारनाथ, हनुमान घाट, गंगा आरती सहित अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए प्रयागराज और फिर अयोध्या का भी भ्रमण करेंगे।

अवैध कब्जा मामले में हाई कोर्ट का एक्शन, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 22 जनवरी तक लगाई रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में कुकरैल नाले के किनारे अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है, इस मामले में हाई कोर्ट ने 22 जनवरी तक रोक लगा दी है। बता दें कि आज ही पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध कब्जा को हटाने के लिए गई हुई थी। दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान

पुलिस ने भीड़ को तितर– बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। नाराज स्थानीय लोगों ने कुकरैल बंधा रोड पर जाम लगा दिया जिससे अयोध्या रोड और महानगर रोड पर भीषण जाम लग गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के समर्थन भाजपा के महानगर मंत्री मंगल झा भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। जिस पर पुलिस ने उन पर भी हल्का बल प्रयोग किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मानें तो मकान अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। दरअसल, कुकरैल रिवरफ्रंट की जद में अकबर नगर की 102 दुकानें और 1200 मकान आ रहे है। इसको लेकर एलडीए ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के आदेश दिए थे। ऐसे में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद गुरुवार सुबह एलडीए भारी पुलिस बल के साथ अकबर नगर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के पहुंचा। इस दौरान एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी, डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक समेत एलडीए के कई विभागीय अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले ही स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद लोग अपने घरों को खाली करना शुरू किया। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है।

रोडवेज-बस ने टेंपो और कार को मारी टक्कर,टेंपो चालक सहित दो लोग घायल

लखनऊ। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह रोडवेज बस की टेंपो और कार से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से टेंपो और कार क्षतिग्रस्त होने के साथ ही टेंपो और कार चालक घायल हो गए। बस चालक मौके से बस छोड़कर फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद जाम लग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पास के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया। जहां पर उसका इलाज चल रहा हैं। पुलिस ने वाहनों को किनारे खड़ा करवाकर यातायात सामान्य कराया। मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे चारबाग की ओर से आ रही रोडवेज बस (यूपी 33 एटी 5332) बस के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए साउथ सिटी पुलिस चौकी के पास रेलवे अंडर पास के नीचे पीजीआई की ओर से आ रही टेंपो (यूपी 32 सीजेड 8334) में साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेंपो अनियंत्रित होकर किनारे हो गई, तो वही पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार (यूपी 32 केबी 8664) बस के अगले हिस्से से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार इतनी तेज थी कि एयर बैग तक खुल गया। इस हादसे में बस चालक और कार चालक दोनों ही अपने वाहन छोड़ कर मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर भीषण जाम लग गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल टेंपो चालक पंकज निवासी कीर्ति खेड़ा सहित टेंपो में बैठी सवारी सोनम गुप्ता निवासी वृंदावन योजना 1 बी, ज्योति निवासी अयोध्या को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया। जहां पर दोनों महिलाओं का प्राथमिक इलाज करने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं चालक को सिविल अस्पताल रेफर कर दिया हैं। साउथ सिटी चौकी प्रभारी धीरेंद्र सिंह का कहना है कि क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को सड़क के किनारे करवाया गया हैं। किसी पक्ष ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी हैं। मामले की जांच पड़ताल की जा रही हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को आयेंगे अयोध्या, दिल्ली के लिए नई ट्रेन को दिखायेंगे हरी झंडी

लखनऊ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के मुताबिक पीएम 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन का शुभारंभ भी 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। हजारों करोड़ों की योजनाएं अयोध्या में तेजी से आकर ले रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन बनानेबपर काम हो रहा है। अभी पहले फेज का काम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन के दूसरे फेज का काम शुरू होगा।

भाजपा नेता ने महिला डीसीपी की कॉलर पकड़ी,

1100 घरों को खाली कराने पहुंची थी पुलिस, लोगों का हंगामा

लखनऊ,(यूएनएस)। लखनऊ के अकबर नगर में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। यहां लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की टीम पुलिस को लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। 500 पुलिसकर्मियों के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की भीड़ आ गई। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो लोग बिगड़ गए। विरोध प्रदर्शन धक्का–मुक्की में बदल गया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष मंगल झा की भी पुलिस से धक्का–मुक्की होने लगी। उन्होंने महिला डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक का कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे अयोध्या रोड पर लंबा जाम लग गया।

वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एलडीए की कार्रवाई पर 4 सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अकबर नगर के निवासियों को जब तक दूसरी जगह बसा नहीं दिया जाता, तक तक किसी को न हटाया जाए। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। दरअसल, एलडीए का कहना है कि अकबर नगर– प्रथम और अकबर नगर–द्वितीय में कुल 1169 निर्माण को अवैध चिन्हित किया गया है। इसमें 111 कॉमर्शियल भी हैं। एलडीए ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 45 दिन पहले नोटिस दिया था। स्थानीय लोगों ने बताया, आज अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही अवैध निर्मित घरों को खाली कराया जाना था। इसके लिए सुबह से ही पुलिस टीम अकबर नगर पहुंच गई। टीम ने सुबह 6 बजे जहां अवैध अतिक्रमण हटाया जाना था, वहां बैरिकेडिंग शुरू कर दी। इसके बाद 8.30 बजे तक पूरी टीम वहां पहुंच गई। सुबह 10 बजे के बाद एलडीए वीसी, नगर आयुक्त और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अफसरों ने कुछ देर डिस्कस किया। इसके बाद अभियान शुरू किया गया। क्योंकि, पहले से ही अभियान तय था। ऐसे में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।

विकास प्राधिकरण के वाइस चांसलर इंद्रमणि त्रिपाठी ने लोगों से कहा, अफवाह फैला रहे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। उनकी बातों पर ध्यान न दीजिए। सब लोग घरों से सामान बाहर निकाल लें। बाहरी लोग यहां से चले जाएं। वहीं, जिन दुकानों पर कार्रवाई होनी है। उन दुकानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। मीटर भी टीम ने उखाड़ लिया है।

फैजाबाद रोड व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने कहा कि कोर्ट की तरफ से जनवरी तक का स्टे मिल चुका है। इसकी वजह से अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से करवाई रुकी हुई है। हालांकि, अभी लिखित कागज आने का इंतजार है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि कुछ देर के लिए कार्रवाई रुकी हुई है। अगर लिखित कागज नहीं आता है, तो फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। दुकानों के ऊपर लगे होर्डिंग्स को तोड़ने के लिए बुल्डोजर से गैस सिलेंडर ऊपर पहुंचाया गया। जिससे होर्डिंग्स को काटा जा सके। स्क। वीसी ने बताया कि होर्डिंग स्ट्रक्चर के गिरने से खतरा हो सकता है। इसलिए इन्हें काटकर धीरे–धीरे हटाया जाएगा। विकास प्राधिकरण के वाइस चांसलर इंद्रमणि त्रिपाठी की अपील के बाद लोग घरों और दुकान से सामान खाली कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्क। की तरफ से दुकान का सामान खाली करने के लिए शाम 5 बजे तक का समय व्यापारियों को दिया गया है।

इधर, दुकान तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही सम्राट फर्नीचर के मालिक सैयद सईदुल बारी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में कई लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। कई लोग हॉस्पिटल में तबीयत खराब होने की वजह से भर्ती कराए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी को कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ममता त्रिपाठी ने घेर लिया। इसके बाद उन्होंने अवैध कब्जा हटाने को लेकर सवाल किया।। ममता चौधरी ने कहा, स्क। वीसी बात नहीं कर रहे हैं। ठंड में अचानक से लोगों को हटाया जा रहा है। नोटिस के जरिए लोगों को कहा गया था कि उन्हें विस्थापित किया जाएगा। अभी तक विस्थापित क्यों नहीं किया गया। क्या लोगों को निशुल्क मकान दिया जाएगा। एलडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ अब तक 113 लोग हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अपील कर चुके हैं। वहीं, 60 और लोगों ने अपील करने की तैयारी कर ली है। इन सभी मामलों की आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोर्ट में उन्होंने सारे कागज जमा किये हैं। जो उन्हें यहां का निवासी बता रहा है। कुकरैल नदी को छोटे रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित किया जाना है। प्रशासन का कहना है कि कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसलिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सौंदर्यीकरण के लिए शासन से अभी कितना बजट मिलना है यह तय नहीं हुआ है। पूरा नक्शा और प्रोजेक्ट DPR बनने के बाद ही नक्शा बनेगा।

सम्पादकीय

असहमति को दबाने पर उतर आये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने शस्त्रागार को समाप्त करने के बाद, भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के मिशन के साथ, अब यह कहावत उछाल रही है कि नरेंद्र मोदी भारत के लौह पुरुष हैं जो पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और उसकी अखंडता को बरकरार रख सके।

निःसंदेह, ऐसी दो घटनाएं हैं जो सीधे तौर पर इस मुद्रा को अनुबंधित करती हैंय सबसे पहले, घुसपैठियों का एक झुंड नए संसद भवन में कूद गया और अंदर धुआं बम फेंक दिया, जिससे व्यापक दहशत फैल गईय और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा के 143 सदस्यों का निष्कासन जो मोदी की अटल, जीवन से भी बड़ी छवि के दावों का खंडन करता है। बीजेपी इकोसिस्टम का नया मंत्र यह है कि मोदी अजेय हैं, उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती और भारत के पास कोई दूसरा नेता नहीं है जो उनका विकल्प बन सके।

दोनों घटनाओं को करीब से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा अति–राष्ट्रवाद के तत्व को उभारने का प्रयास कर रही है। घुसपैठ के मामले में आश्चर्य की बात यह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक दिखावा करने वाले दोनों शीर्ष नेताओं मोदी और अमित शाह ने निष्क्रिय और बहरा कर देने वाली चुप्पी बनाए रखना पसंद किया है। संसद में बयान देना अत्यंत संवैधानिक और कानूनी महत्व का मामला है। लेकिन घर से बाहर मीडिया को दिए गए बयान पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जाहिर है, मोदी और शाह सदन में ऐसा कोई बयान देना पसंद नहीं करते जिससे उनका राजनीतिक दोहरापन उजागर हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके कार्य उस अहंकार को दर्शाते हैं जिसने उन्हें इस मनमाने तरीके से कार्य करने और संसद और इसकी पवित्रता के प्रति पर्याप्त अनादर प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया। इसके अतिरिक्त, यह दावा करना कि विपक्षी सांसदों का निलंबन आसन्न हो गया था क्योंकि उन्होंने सदन की छवि खराब की थी और सदन के कामकाज में बाधाएं पैदा की थीं, क्या यह अपने आप में एक भद्दा मजाक है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी जानबूझकर संसद में बयान देने से दूर रहे हों। पिछली बार उन्होंने इस हथकंडे का सहारा तब लिया था जब उन्होंने सदन के बाहर मणिपुर पर बयान दिया था। बाद में विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी द्वारा आलोचना किए जाने के बाद, उन्होंने एक सिलसिलेवार संदर्भ दिया। अब निचले सदन में बचे विपक्षी भारत गुट के प्रमुख चेहरों में कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय शामिल हैं। संसद की कार्यप्रणाली के 70 साल लंबे इतिहास में एक या दो दिन के भीतर सैकड़ों विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित किए जाने का जिक्र नहीं है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर शविपक्ष–विहीनश संसद में प्रमुख कानूनों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कैसी विडंबना है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस बात से आहत हुए कि विपक्ष के नेता खड़गे ने उनके कक्ष में उनसे मिलने के उनके आदेश का जवाब नहीं दिया। धनखड़ ने अपने इनकार को अपना अपमान बताया। सदन फिर से शुरू होने के बाद खड़गे बोलने की अनुमति के लिए हाथ उठाते रहे, धनखड़ ने उन्हें मौका नहीं दिया और इस टिप्पणी के साथ सदन को स्थगित कर दियारू श्यह बहुत दर्दनाक दिन है। सदन को चिल्लाने वाली ब्रिगेड में तब्दील कर दिया गया है। मैंने गहरी पीड़ा के साथ यह (निर्णय) लिया है। लेकिन संयोगवश उनकी टिप्पणी 45 सांसदों के निलंबन के बाद आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों द्वारा शाह के बयान और उनके इस्तीफे की मांग को सदन की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा. कुछ विपक्षी सांसद अपनी मांगें लिखी तख्तियां भी लिए हुए थे। संसदीय कामकाज में यह कोई असामान्य बात नहीं है। तख्तियां ले जाना निश्चित रूप से उस सदन के लिए खतरा नहीं है जिसके वे सदस्य हैं। निलंबन से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया और विपक्षी सदस्यों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और सदन के नेता पीयूष गोयल ने दावा किया कि यह कार्रवाई आवश्यक थी क्योंकि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का अपमान किया था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार की हर कार्रवाई एक सोची–समझी साजिश का हिस्सा है। जब सरकार तथ्यों पर आधारित व्यापक जवाब देने में विफल रहती है तो विपक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है। जाहिर है, गोयल का कांग्रेस और भारतीय गुट के सदस्यों पर अपने आचरण से देश को शर्शिंदाश करने और जानबूझकर संसदीय कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाना निराधार है। गोयल ने कहा संसद को सुचारू रूप से नहीं चलने देना स्पष्ट रूप से उनकी पूर्व नियोजित रणनीति थी, यह देखते हुए कि जम्मू–कश्मीर और पुदुचेरी में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा गया था, लेकिन विपक्षी सदस्य विरोध कर रहे थे चर्चा की अनुमति नहीं दी। गोयल को भाजपा के संरक्षक लालकृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगी अरुण जेटली की कार्यप्रणाली से सीख लेनी चाहिए थी, जब वे दोनों विपक्ष में बैठे थे और आडवाणी नेता थे। अपने समय की कांग्रेस सरकारों को शर्मिंदा करने के लिए संसद की कार्यवाही में बाधा डालना आडवाणी और अन्य की पसंद का साधन था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो भारत ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचीं, ने सांसदों के खिलाफ कार्रवाई को लोकतंत्र का मजाक बताया। उनके पास गुस्सा होने का हर कारण है। कुछ बीजेपी नेता टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं. यहां तक कि कुछ जांच अधिकारी भी टीएमसी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी खेमे में यह भावना घर कर रही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मोदी और शाह विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए जांच संस्थाओं का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, यही कारण है कि वे सामूहिक निलंबन को खूनखराबा और हत्या करार देते हैं। लोकतंत्र, असहमति को दबाने के लिए तनशाही (तानाशाही) का एक उच्च स्तर है। ममता ने स्पष्ट कहा, हम चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो। इसीलिए हम उल्टी सीधी (मूर्खतापूर्ण) टिप्पणियां नहीं करने जा रहे हैं। हम एबोल्टाबोल (बकवास) नहीं बोलते. .. यह एक सुरक्षा चूक है। (केंद्रीय) गृह मंत्री (अमित शाह) पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं। श्यह बहुत गंभीर मामला है, इसमें कोई शक नहीं... उन्हें मामले की जांच करने दीजिये। क्योंकि हम किसी भी सुरक्षा मामले पर समझौता नहीं करते हैं। विपक्षी सदस्यों द्वारा बयान की मांग करने का प्राथमिक कारण उनकी आशंका है कि मोदी और शाह इस घटना का दुरुपयोग भाजपा विरोधी नेताओं और व्यक्तियों को फंसाने के लिए कर सकते हैं। मोदी ने पहले ही एक हिंदी दैनिक को दिए अपने साक्षात्कार में कहा था कि एजेंसियां सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच कर रही हैं और कड़े कदम उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे के लोगों और उनके इरादों की तह तक जाना जरूरी है। इस साल की शुरुआत में जब संसद एक नए घर में स्थानांतरित हुई, तो मोदी ने एक श्नई चेतनाश जगाने की बात कही थी। अब 13 दिसंबर की घटना के मद्देनजर कुछ सदस्यों को लगता है कि मोदी असहमति को दबाने के लिए गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इसी तरह गुजरात में बाढ़ पर बहस की मांग करने पर विधायकों को निलंबित कर दिया गया थाय सरकार पर घोटालों में शामिल होने और कॉर्पोरेट घरानों को अनुचित मदद देने का आरोप लगाने के लिएय एक धोखेबाज पुलिस अकादमी में कैसे पहुंचा, इस पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, यह गुजरात मॉडल का विस्तार है, जिसमें विपक्ष को बाधा के रूप में देखा जाता है। सदस्यों के निलंबन को उचित ठहराने के लिए दो शब्द गरिमा और मर्यादा– गरिमा और अनुशासन– लोकसभा और राज्यसभा में गूंजे। निलंबित राजद सांसद मनोज झा के अनुसार, यह संसदीय मर्यादा की एक सत्तावादी व्याख्या है।

ज्ञानवापी हिन्दू आस्था का प्रश्न

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चल रही कानूनी लड़ाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हिन्दू पक्ष को काफी संतोष मिला है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षणध्के खिलाफ याचिका समेत मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं कोध्ठुकरा दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 1991 के वाराणसी कोर्ट में दायर मुकदमे को सुनवाई योग्य मानते हुए वाराणसी की अदालत को 6 माह के भीतर फैसला देने का निर्देश दिया है। वर्ष 1991 में एक केस फाइल किया गया था। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। यह केस सोमनाथ व्यास, रामनारायण शर्मा और हरिहर पांडे की ओर से दाखिल किए गए थे। इस केस में दावा किया गया था कि मस्जिद जहां बनी है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है। इसलिए मुस्लिम धर्मस्थल को हटाकर उसका कब्जा हिन्दुओं को सौंपा जाए। घ्मस्जिद को लेकर पहलाध विवाद 1809 में हुआ था जो साम्प्रदाध्यिक दंगों में तब्दील हो गया था। अदालत में एक मुकदमा 1936 में भी दायर हुआ था जिसका निर्णय 1937 में आया। फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर हाईकोर्ट ने मस्जिद को वक्फ प्रोपर्टी माना। 12 सितम्बर, 2022 को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी–देवताओं की पूजा की मांग को लेकर दायर की गई पांच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दीं। जब 1991 में ज्ञानवापी मामले में पहला मुकदमा दायर हुआ तो उसके कुछ महीने बाद सितम्बर 1991 में तत्कालीन पी.वी. नघ्रसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल कानून बना दिया। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल छह महीने के लिए ही होगी। उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में शृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब 32 वर्ष बाद मुकदमे की सुनवाई का आदेश दिया है और कहा है कि 1991 का उपासना स्थल कानून इस घसिविल वाद में बाधित नहीं है। अब जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जा चुकी है और उसी के आधार पर स्वामित्व विवाद का हल निकल सकेगा और करोड़ों हिन्दुओं की आस्था जीवंत हो उठेगी। अब वाराणसी कोर्ट 6 माह में अपना फैसला सुनाएगा। हिन्दू पक्ष के वकीलों को उम्मीद है कि अब वजुखाने का सर्वे भी होगा। मेरा अभी भी यह दृढ़ मत है कि काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित ज्ञानवापी क्षेत्र को मुस्लिम बन्धुओं को हिन्दुओं को सौंप देना चाहिए और स्वतन्त्र भारत की एकता व 'गंगा–जमुनी' तहजीब में इजाफा करने के लिए अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। काशी या बनारस हिन्दू मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शंकर द्वारा बसाया गया वह स्थान है जिसमें शहनाई वादन के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने अपनी धुनों से भोलेनाथ को मनाया और शंकर शंभू जैसे महान कव्वालों ने "हजरत मोहम्मद सलै–अल्लाह–अले–वसल्लम" की शान में 'नात' गाया। काशी के विश्वनाथ धाम के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी संग्रहालय में सुरक्षित हैं कि 1669 में औरंगजेब ने इसका विध्वंस करने का फरमान जारी किया था। इसी प्रकार उसने मथुरा के केशवदेव मन्दिर को भी क्षति पहुंचाने का आदेश दिया था। बेशक यह उस दौर की राजनीति में राजशक्ति दिखाने की कोई रणनीति रही होगा जबकि औरंगजेब के शासन में पूरे मुगल सम्राटों के शासन के मुकाबले सर्वाधिक 'हिन्दू मनसबदार' थे। मगर यह इतिहास का सच तो है ही अतः मुसलमानों को इसे स्वीकार करना चाहिए और भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए फराखदिली दिखानी चाहिए। ज्ञानवापी की दरो दीवार यही कहती है कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई तो इस्लाम की नजर में भी नाजायज है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कमेटी ने यह भी कहा है कि मस्जिद को आसानी से तश्तरी में सजा कर नहीं देंगे। अब जबकि इंसाफ नहीं हो रहा तो सड़कों पर उतरने के हालात भी बन सकते हैं। अभी भी समय है कि दोनों सम्प्रदाय बैठकर मुद्दे को सुलझाएं। अयोध्या की तर्ज पर मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं ओर भूमि भी दी जा सकती है।

ठिठुरता गणतंत्र, आहत महामहिम

कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरु हो गई है। गण कांप रहे हैं, तंत्र पर पाला पड़ गया है। परसाई जी आज होते तो शायद ठिठुरते गणतंत्र में आहत महामहिम की व्यथा–कथा पर भी लिखते कि कैसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों के हक मारे जा रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि माननीय मोदीजी क्यों देश में भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं। बेचारे राम कब से अपने घर के बाहर हैं। सोचने वाली बात है कोई घर से बाहर रहेगा तो कैसे राज कायम करेगा। इसलिए मंदिर में श्री राम का विराजना और संसद में प्रधानमंत्री की आसंदी पर नरेन्द्र मोदी का विराजना जरूरी है। जब ऐसा होगा, तभी राम राज कायम होगा। अभी तो घोर कलजुग चल रहा है। सनातन धर्म को चुनौती दी जा रही है। क्या पिघले हुए सीसे अधर्मियों के कान में डालने की जगह नालियों में बहा दिए गए हैं। इसलिए इन्हीं नालियों से गैस बनाने का गुर मोदीजी सिखा रहे थे। कितने ज्ञानी और दूरदर्शी हैं वे, हर बात वक्त से पहले समझ जाते हैं। उन्होंने 2001 में ही देख लिया था कि आने वाले सालों में देश का क्या हाल होने वाला है। चाय बेचते–बेचते संन्यास लेने और गुफा में चश्मा लगाकर तपस्या करने का यही तो लाभ है कि आप इहलोक–परलोक सबके संकेत समझ जाते हैं। उन्हें अहसास था कि सदियों से चले आ रहे लोकतंत्र को आजादी के बाद मिले लोकतंत्र से चुनौती मिल सकती है। नेहरू एंड कंपनी ने आजादी और अधिकारों के नाम पर निचले तबके के लोगों को भी सिर चढ़ा लिया था। तभी तो एक बूढ़ी महिला ने नेहरू के गिरेबान को पकड़ कर सवाल कर लिया था कि आजादी मिली, तुम प्रधानमंत्री बन गए तो हमें क्या मिला। बदले में नेहरू ने जवाब दिया था कि आपको ये मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ कर खड़ी हैं।

बताइए भला, ये भी कोई बात हुई कि प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया जाए और वो बुरा भी न माने। बुलबुलसवार वीरों ने ऐसी आजादी की कल्पना कतई नहीं की थी। इसलिए आजादी की लड़ाई की जगह माफी मांगने पर जोर दिया गया। लेकिन इन कांग्रेसियों को कौन समझाए। आजादी के लिए लड़ते रहे, मरते रहे और जब आजादी मिली तो ऐसा लोकतंत्र और संविधान ले आए कि नीच–ऊंच सब सपाट करने की बात होने लगी। इसलिए अभी सरकार जितने तरह से हो सके, देश को ये समझा रही है कि असली आजादी 15 अगस्त के बाद मिली है, उसके पहले तो देश नेहरू का गुलाम रहा। मोदीजी जो बात–बात में नेहरू की गलतियां निकालते रहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो भी नेहरू के नक्शेकदमों पर चल रहे होते तो फिर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात कैसे होती। बिचारे ठिठुरते गणों ने कितने सपनों से मोदीजी को एक नहीं दो–दो बार सत्ता पर बिठाया है, ताकि देश में हिंदुओं का शासन कायम हो सके। मोदीजी को जुमलेबाज कहने वाले देशद्रोही ही नहीं गणद्रोही भी हैं। उन्हें मोदीजी को जुमलेबाज कहने की जगह देखना चाहिए कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए कैसे वे दिन–रात एक करके काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब, एक के बाद दूसरा मंदिर बनवाने से है। अयोध्या की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब काशी, मथुरा कतार में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कभी महाकाल, कभी तिरूपति, कभी अक्षरधाम, कभी केदारनाथ, कहीं न कहीं मोदीजी पूजा–पाठ करते दिख ही जाएंगे। सनातन का महात्म्य इसी में है कि देश का प्रधानमंत्री दिन–रात भगवान की पूजा में लगा दे। पहले के प्रधानमंत्रियों ने, यानी 1947 से लेकर 2014 तक के प्रधानमंत्रियों ने देश को गुमराह किया कि हम आजाद हैं। पुराने संसद भवन से सेंगोल गायब था, इसलिए सांसदों को इतनी छूट मिली हुई थी कि वे सवाल–जवाब कर सकें। सांसदों को सिर पर चढ़ने देने की गलती नेहरूजी ने खूब की, इसलिए उनके गंजे सिर तक पर संसद में तंज कसे गए। इससे जनता को और मुगालता हुआ कि हम आजाद हैं और देश में लोकतंत्र है। नेहरू की गलतियों को उनके आगे के प्रधानमंत्रियों ने भी जारी रखा। इसलिए शून्यकाल, प्रश्नकाल, हर तरह के काल में सवाल पूछे गए और सरकार ने जवाब दिए। हद ही हो गई थी। इसलिए मोदीजी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाकर बिल्कुल सही किया, तभी तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत देश को समझा पाए कि हमारे यहां टू मच डेमोक्रेसी है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबको अधिकार का अ, बगावत का ब, सम्मान का स सीखा दिया गया था। जब हमारे पुराणों, मनु स्मृति में इन्हें दबाकर रखने कहा गया है तो फिर इस व्यवस्था को बदलने की क्या जरूरत है। इससे पहले कि पानी सिर के ऊपर से निकलता, टू मच डेमोक्रेसी को आखिरी विदा देने का फैसला ले लिया गया।

नए संसद भवन में सेंगोल को कितने श्रद्धाभाव से पुजारियों के दिशा–निर्देशों पर मोदीजी ने स्थापित किया था। उस सेंगोल को प्रयागराज के संग्रहालय की तरह सजावट की वस्तु बनाकर तो रखना नहीं था। इसलिए अब उसका इस्तेमाल शुरु हुआ है। जैसे नए चाकू की धार तेज होती है और बड़ी तेजी से सख्त दिखने वाले गाजर–मूली को काट देती है, कुछ इसी अंदाज में सेंगोल की छांव तले लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से आवाज उठाने वाले सांसदों को बाहर किया गया। लेकिन सांसदों की धृष्टता इस पर भी खत्म नहीं हुई। संसद परिसर में बैठकर ही राज्यसभा सभापति की नकल उतारना और नकल उतारने वाले का वीडियो बनाना शुरु कर दिया। एक तो दिल्ली की सर्दी, ऊपर से ठिठुरते हुए गणतंत्र की चिंता और इसमें सांसदों का ऐसा व्यवहार, महामहिम का आहत होना स्वाभाविक था। उन्होंने भी टू मच डेमोक्रेसी की तरह कह दिया कुछ तो सीमा होती होगी। कुछ जगह तो बख्शो। सही बात है जो काम प्रधानमंत्री मोदी का है, अब उसे दूसरे सांसद करने लग जाएंगे, तो ये मोदीजी के अधिकार क्षेत्र का सरासर उल्लंघन है। संसद भवन के भीतर आंख मिचमिचाने की मिमिक्री करनी हो या बाहर ताली बजा–बजाकर सवाल पूछना हो, ये सब मोदीजी ही कर सकते हैं। किसी और को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। इसलिए इस घटना से राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के साथ–साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई नेता आहत हो गए। यहां तक कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने भी इस पर अपनी निराशा प्रकट कर दी।अब लग रहा है कि वाकई देश नए सिरे से आजाद हुआ है। क्योंकि अब लोगों को कपड़े देखकर मारने–पीटने, सिर पर पेशाब करने, नग्न करके घुमाने, गाड़ी से कुचलने, रस्सी बांधकर घसीटने, सरेआम अपशब्द कहने, भूखे, बिना इलाज के मरते देखने पर माननीयों की भावनाएं बिल्कुल आहत नहीं होती। लेकिन उन्हीं लोगों के चुने लोग संसद भवन में सवाल पूछें और जवाब की जगह निलंबन मिलने पर अपना रोष नकल उतार कर दिखाएं तो सारे माननीयों के मन में निराशा छा जाती है कि आखिर इस तरह देश में कैसे राम राज और मोदी राज आएगा। निलंबन के बाद अब निलंबित सांसदों के संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है, उन्हें संसदीय समितियों की बैठकों से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद दूसरी आजादी को बचाए रखने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या सख्ती बरती जाती है, क्या इन सांसदों के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगती है या राज कायम रखने के लिए चुनाव ही रोक दिया जाता है, ये देखना होगा। तय है कि माननीयों के मन में छाई निराशा को दूर करने के लिए अभी कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। देखना यह है कि ठिठुरते हुए गण अपने हाथ–पैर–बुद्धि सीधे कर गर्मी लाने का उपाय तलाशेंगे या फिर भजन करके ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता ढूंढेंगे।

संसद पर हमला, अब और तब

यह एक इमारत जरूर है पर उससे भी महत्वपूर्ण यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, उसका प्रतीक है। इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संसद है तो लोकतंत्र है, लेकिन इसी भवन में 13 दिसम्बर को दो नौजवान दर्शक गैलरी से लोकसभा के सदन के बीच कूद पड़े और पकडे जाने से पहले अंदर धुएं के कनस्तर से पीला धुआं फैलाने में सफल रहे। दो और साथी बाहर पकड़े गए। यह धुआं हानिकारक नहीं था पर अगर उनके पास इसकी जगह बारूद होता तो क्या होता? उस दिन संसद ने 22 वर्ष पहले हुए हमले में संसद की रक्षा करते मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और इसी दिन ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमला करने की धमकी दी थी पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था लापरवाह पाई गई। अपराधियों को वहां ही पकड़ लिया गया पर सवाल तो है कि हमारे यहां 'सब चलता है' की संस्कृति क्यों है कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने नए संसद भवन की सुरक्षा का कुछ नौजवान मजाक बना गए? जब नया भव्य भवन बनाया गया तो यह बताया गया कि बिल्कुल सुरक्षित होगा, लेकिन कुछ ही महीने में पता चल गया कि भवन बदला, लापरवाह मानसिकता नहीं बदली। इस बार घुसपैठियों के आतंकवादियों के साथ सम्बंध नहीं हैं, न ही वह पेशेवर अपराधी ही हैं, पर अगर होते तो? अब आठ सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन यह भी छुपा है कि संसद में सुरक्षा कर्मियों की 40 प्रतिशत जगह खघली है। यह कैसे हो गया? नई इमारत में दर्शक गैलरी से सांसदों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं जिससे वहां से छलांग लगाना आसान है जबकि पुराने भवन में वह पीछे थी। मुझे याद है कि पहली बार जब मैं संसद की कार्यवाही देखने गया तो सामने लगे जंगले पर मैंने पैर रख दिया। एक सुरक्षाकर्मी तत्काल पहुंचा कि ऐसा करना मना है। ऐसी चौकसी कहां गई? अब तो यह लोग जूतों में छिपाकर स्मोक कैन ले गए और कोई मशीन या कोई गार्ड उन्हें पकड़ नहीं सका। अब शायद दर्शक गैलरी के सामने शीशा लगाया जाएगा ताकि कोई और फिर कूद न सके। डिजाइन में त्रुटि का यह ही इलाज है। संसद और सांसदों को सुरक्षित रखने के लिए सारे उचित कदम उठाए जाने चाहिए पर इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि जनता, जो वास्तव में इसकी मालिक है, का इस बहाने प्रवेश सीमित कर दिया जाए। जनता को मौका मिलना चाहिए कि वह देख सकें कि उसके सदन की कार्यवाही कैसे चल रही है? दुनिया की कई संसद में तो जनता के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। कनाडा की संसद गर्मियों में अपने द्वार लोगों के लिए खोल देती है ताकि लोग वहां बाग में योगा कर सकें। जर्मनी की संसद की इमारत बुंडेस्टैग का गुंबद शीशे का बना हुआ है ताकि लोग ऊपर से देख सकें कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सारा प्रभाव खुलेपन का है। हां, कई संसद में दर्शक गैलरी से पैमफलेट फेंकने की घटनाएं हो चुकी हैं। शीशा लग जाने के बाद यह सम्भावना तो समाप्त हो जाएगी पर यह जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि संसद का खुलापन सीमित नहीं होना चाहिए। संसद न केवल लोगों की है पर लोगों के लिए भी है।

इन लोगों ने यह तमाशा क्यों किया? क्या वह केवल हताशा में सरकार का ध्यान बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ले जाना चाहते थे या कोई और खघ्तरनाक मकघ्सद था, यह तो जांच ही बताएगी पर यह दिलचस्प है कि यह सब युवा देश के अलग–अलग हिस्सों से हैं। कोई उत्तर प्रदेश से तो कोई बिहार से तो कोई कर्नाटक से तो कोई महाराष्ट्र से है। संसद भवन के बाहर पकड़ी गई लड़की नीलम सिंह हरियाणा से है। वह बहुत पढ़ी–लिखी है और सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी जबकि उत्तर प्रदेश का सागर शर्मा 12वीं तक ही पढ़ा है। बिहार का ललित झा टीचर है। महाराष्ट्र का अमोल धनराज शिंदे सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था जबकि कर्नाटक का मनोरंजन देवाराजे गौड़ा इंजीनियरिंग कर चुका है। इतनी विविध और असमान पृष्ठभूमि वाले यह नौजवान इकट्ठे कैसे हो गए? इन सबके बारे बताया जाता है कि वह फेसबुक पर 'भगत सिंह फैन क्लब' से जुड़े हुए हैं। यह दिलचस्प है कि भगत सिंह को फांसी लगे 92 साल के बाद भी वह देश के युवाओं के एक वर्ग के आदर्श हैं। पंजाब में तो हर सरकारी दफ्तर में उनकी तस्वीर लगी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पीली पगड़ी डालते हैं जबकि कोई प्रमाण नहीं कि भगत सिंह ने कभी पीली पगड़ी डाली थी। नीलम सिंह ने फेसबुक पर लिखा है, ' नए भारत के निर्माण के लिए चलो भगत सिंह के रास्ते'। पृष्ठभूमि में भगत सिंह की तस्वीर लगा सागर शर्मा ने फेसबुक पर लिखा है, 'जिन नौजवानों ने कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज ही अकल से अंधा बनाने की कोशिश हो रही है', लेकिन क्या यह लोग भगत सिंह और उनकी वैचारिक गहराई को समझते भी हैं? ठीक है उस महान शहीद ने असेम्बली में बम फेंकते समय कहा था कि 'बहरे कानों को सुनाने के लिए ऊंचे विस्फोट की जरूरत है', पर जिन कानों की वह बात कर रहे थे वह फिरंगी कान थे। वह साम्राज्यवादी कान थे। वह अपनी संसद में कभी ऐसी हरकत न करते। जिन्होंने संसद में हरकत की है उनके खघ्लिाफ तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना संसद भवन में, या कहीं और, दोहराई जाए। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि उस जन प्रतिनिधि जिसके गैरजिम्मेदार आचरण के कारण संसद की सुरक्षा और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ी है, के प्रति भी उदारता न दिखाई जाए। इन अभियुक्तों को संसद का प्रवेश पास भाजपा के मसूर से सांसद प्रताप सिम्हा ने दिलवाया था। उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संसद के नियमों के बारे एम.एन. कौल और एस. एल. शकधर की किताब में लिखा है, "एक सांसद को दर्शक पास के लिए आवेदन उन्हीं के लिए देना चाहिए जिन्हें वह निजी तौर पर जानता हैश्सांसद को यह प्रमाणित करना है कि दर्शक मेरा सम्बंधीध निजी दोस्तध जिसे मैं निजी तौर पर जानता हूं, और मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं" इसलिए जो हुआ उसकी जिम्मेवारी से प्रताप सिम्हा बच नहीं सकते पर अभी तक उनके खिलाफ कोई जांच हुई हो, इसकी कोई खबर नहीं। अगर कोई बड़ी साजिश है तो सांसद से भी पूछताछ होनी चाहिए। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को अपना संसदीय लॉगइन साझा करने के अपराध में संसद से निष्कासित किया गया था। निश्चित तौर पर प्रताप सिम्हा का अपराध महुआ मोइत्रा से बहुत अधिक गम्भीर है। उनके कारण संसद की सुरक्षा भारी खतरें में पड़ गई थी। 22 साल पहले 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हमला हुआ था। कई लोग कह रहे हैं कि वर्तमान घटना उससे भी अधिक गम्भीर है। कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव वी. बालाचन्द्रम लिखते हैं, "इस बार जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी अपराधी संसद के दिल तक पहुंचने में सफल रहे हैं। यह इसे 2001 की घटना से अधिक गम्भीर बना देती है, क्योंकि तब आतंकवादी इमारत के अंदर तक पहुंचने में सफल नहीं हुए थे"। उनका कहना है कि अगर गैस के कनस्तर की जगह उनके पास ग्रेनेड होता तो क्या हालत होती? पर मेरी राय उनसे अलग है, क्योंकि ग्रेनेड या कोई हथियार नहीं थे इसलिए यह घटना उतनी गम्भीर नहीं है। 2001 में तो बाकायदा पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी हमला हुआ था। उस दिन आतंकवादी सफेद एम्बेसेडर कार में आए थे। कार में ड्राइवर और पांच आतंकी थे। यह तो सौभाग्य है कि अफरा–तफरी में उस कार की टक्कर उपराष्ट्रपति की कार से हो गई और सुरक्षाकर्मी एलर्ट हो गए। आतंकियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी पर उससे पहले सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी मेन गेट बंद करने में सफल

समय के उपयोग पर आकड़ों के संग्रहण के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन

आकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक : अंशिका

लखनऊ,(यूएनएस)। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय क्षेत्र संकार्य प्रभाग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार समय के उपयोग पर आकड़ों के संग्रहण के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसम्बर तक चलेगा। क्षेत्र अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 21 से 22 दिसम्बर के दौरान दो दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर यानि आरटीसी का आयोजन राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन आज एनएसएसओ भवन विकास नगर लखनऊ के तृतीय तल पर स्थित सभा कक्ष में सहायक निदेशक राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ अंशिका बाजपेई ने किया। अंशिका बाजपेई ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए समय के उपयोग यानि टीयूएस के वार्षिक सर्वेक्षण के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। सुश्री बाजपेई ने बताया कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक क्रियाकलापों में पुरुषों, महिलाओं और अन्य समूहों की भागीदारी का आकलन करना है। यह सर्वेक्षण अवैतनिक देखभाल क्रियाकलापों, अवैतनिक स्वयंसेवी कार्य, परिवारों के सदस्यों के अवैतनिक घरेलू सेवा प्रस्तुत करने संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। यह परिवार के सदस्यों के अध्ययन, समाजीकरण, फुरसत के क्रियाकलापों, खुद की देखभाल संबंधी क्रियाकलापों आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नीति–निर्माण के लिए उन्होंने आगे बताया कि इस विषय पर सर्वेक्षण प्रथम दौर जनवरी 2019 दृ दिसम्बर 2019 में किया गया था। सुश्री बाजपेई ने आर्थिक विकास की योजना बनाने और बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यों के समय व्ययन पर विश्वसनीय आंकड़ों को एकत्र करने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रभावपूर्ण क्षेत्र कार्य के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर के महत्व को आगे बताते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किए जा रहे आकड़ों की उच्च स्तर की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया। ये आकड़े ई–सिग्मा सीएपीआई सॉफ्टवेयर पर टैबलेट के द्वारा एकत्र किये जाएंगे जिससे उनके परिणाम शीघ्र जारी किए जायेंगे। सुश्री बाजपेई ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सर्वेक्षण की सफलता और उससे प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता, जनमानस के सहयोग और सूचकों द्वारा प्रदान की गई तथ्यपुरक जानकारी पर निर्भर करती है। सुश्री बाजपेई ने सभी परिवारों से सर्वेक्षण के दौरान सहयोग करने की अपील की और जब भी सर्वेक्षण कर्मी उनके पास आएंगे, वे उनका पूरा सहयोग कर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल विकास योजना के नीति निर्धारण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। इस प्रकार एकत्र किए गए आकड़ों और सर्वेक्षण के आधार पर आए परिणाम केंद्र, राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे।सहायक निदेशक उप क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर शिखा राय ने अपने संबोधन में आँकड़ो की गुणवत्ता बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि चूँकि यह कार्य सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा एवं आँकड़े सीधे टैबलेट पर ई–सिग्मा प्लेटफॉर्म के सीपीएआई सॉफ्टवेयर के द्वारा एकत्रित किए जायेंगे। ऐसे में अधिकारियों एवं क्षेत्र कर्मियों को क्षेत्र कार्य के दौरान सजग रहने की आवश्यकता है द्यवरिष्ठ संख्यिकीय अधिकारी योगेश भारती ने बताया कि दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ और उप क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मध्यांचल कार्यालय लखनऊ के 40 अधिकारियों,क्षेत्र कर्मियों ने भाग लिया।

एक माह बाद विराजमान होंगे रामलला

राममंदिर पर 7.5 स्केल की तीव्रता के भूकंप का भी नहीं होगा असर

रोजाना एक लाख भक्त कर सकेंगे दर्शन

लखनऊ,(यूएनएस)। भगवान श्रीराम आ रहे हैं। उनके स्वागत को अयोध्या बेताब है। हर कोई 22 जनवरी के इंतजार में है। अयोध्या का आंगन सज रहा है। देश–विदेश के वास्तुविद, शीर्षस्थ कंपनियों के इंजीनियर और दूसरी विधाओं के विशेषज्ञ राममंदिर को आकार दे रहे हैं।सामान्य मंदिरों से इतर गहरी नींव, मजबूत आधार के साथ यह केवल पत्थरों से बना होगा। महज कुछ साल तक चलने वाली सीमेंट जैसे दूसरे पदार्थों का रंचमात्र प्रयोग नहीं हो रहा। रामलला का घर भूकंपरोधी होगा। एक हजार साल से ज्यादा समय तक अक्षुण्ण रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में प्रचलित मंदिरों की नागर शैली में सरयू के किनारे बन रहा राममंदिर भौतिक विशिष्टताओं की खान है। राममंदिर पूर्व मुखी है। मंदिर में तीन तल हैं। ऊंचाई 161 फीट है। प्रत्येक तल की ऊंचाई 20 फीट होगी। पूरब और पश्चिम दिशा में मंदिर 350 फीट लंबा होगा। उत्तर–दक्षिण दिशा में 235 फीट चौड़ा होगा। मंदिर में पांच गुंबद यानि मंडप होंगे, जिसमें से अब तक तीन मंडप तैयार हो चुके हैं। चौथे मंडप का काम चल रहा है।राममंदिर निर्माण में 3500 कारीगर व मजदूर लगाए गए हैं। ये मजदूर राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हैदराबाद आदि राज्यों के हैं। राममंदिर निर्माण का काम रात में भी होता है। इसके लिए दो शिफ्ट में आठ–आठ घंटे मजदूरों की ड्यूटी लगाई जाती है। हैदराबाद के कारीगर रामसेवकपुरम में राममंदिर के दरवाजों का निर्माण कर रहे हैं।राममंदिर की खिड़कियां,

चौखट, दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी से बन रहे हैं। राममंदिर में कुल 42 दरवाजे लगाए जा रहे हैं। ये सभी दरवाजे सागौन की लकड़ी से बन रहे हैं। मंदिर निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान के मिर्जापुर और बंसीपहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और नक्काशीदार संगमरमर से हुआ। गुलाबी पत्थरों की चमक सैकड़ों साल तक रहती है। मंदिर की नींव में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक का वजन दो टन है। ग्रेनाइट पत्थर ठोस होता है। पानी के रिसाव को सोख लेता है। इसलिए नींव की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। राममंदिर की नींव 50 फीट गहरी रखी है। इसे बनाने में सात महीने लगे थे। नींव में 47 परतें बिछाई गई हैं। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर को कम से कम एक हजार साल तक किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता नहीं होगी। दावा है कि 7.5 तीव्रता के भूकंप का असर राममंदिर पर नहीं होगा। बाढ़ से बचाने के लिए मंदिर के चारों दिशाओं में 50 फीट गहरी सुरक्षा दीवार बन रही है।रामलला की अचल मूर्ति 51 इंच की होगी। कमल के आसन पर रामलला विराजेंगे। हाथ में धनुष–बाण होगा। आसन सहित प्रत्येक मूर्ति की ऊंचाई लगभग सात फीट होगी। राममंदिर का एक अन्य आकर्षण यह है कि हर रामनवमी को सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। सूर्य के प्रकाश को रामलला के माथे पर प्रतिबंधित करने के लिए एक उपकरण भी गर्भगृह में लगाया जा चुका है। इस पर इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं।राममंदिर निर्माण की संपूर्ण तकनीक और इस ऐतिहासिक काम में लगी तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट को लेकर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। डॉक्यूमेंट्री के लिए अमिताभ बच्चन अपनी आवाज दे रहे हैं। मंदिर बनने के बाद रिलीज होगी। राममंदिर में रोजाना एक लाख भक्त दर्शन–पूजन कर सकेंगे। परिसर में आस्था के साथ आधुनिकता की झांकी दिखेगी।आधुनिक सुविधाओं वाले प्रकल्प, सीवर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट से लेकर यात्री सुविधा केंद्र, पार्किंग, चिकित्सालय, सामुदायिक रसोई की व्यवस्था होगी।

मिमिक्री पर किरकिरी, उप राष्ट्रपति के अपमान पर गरमाया जाट संगठन, अखिलेश और जयंत की रणनीति को लगेगा बड़ा झटका

लखनऊ, (यूएनएस)। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के बाद पूरे देश में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा के सभी बड़े नेता एक के बाद एक इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में उप राष्ट्रपति का अपमान करना विपक्ष को भारी पड़ रहा है। जाट समुदाय की ओर से इस घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वहीं, भाजपा इस मामले को लेकर ओबीसी के अपमान के मुद्दे को उठाया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे खुद के दलित होने की बात करते हुए न बोलने देने की बात करने लगे हैं। संसद के सुरक्षा में चूक का मसला अब जातीय लड़ाई तक पहुंच गया है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगियों को यूपी में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अखिलेश यादव का च्व। (पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक) फ्रंट और जयंत चौधरी की जाट–मुस्लिम एकता की कवायद पर चोट पहुंचती दिख रही है।उप राष्ट्रपति के अपमान का मामला देखते ही देखते जातीय अपमान पर पहुंच गया। जाट संगठनों ने इस मामले में उप राष्ट्रपति का समर्थन किया। इसे समाज के अपमान के रूप में पेश किया गया। विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। सबसे अधिक असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी की आबादी में जाट जनसंख्या करीब दो फीसदी है। लेकिन, पश्चिमी यूपी में यह आबादी बड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती है। इस वर्ग से कई अन्य जातियां जुड़ती हैं, जो जाट वोट बैंक के साथ– साथ आगे बढ़ती हैं। पश्चिमी यूपी की 22 लोकसभा सीटों पर जाट जनसंख्या जीत–हार का अंतर तय करती है। इन सीटों पर किसान आंदोलन के बाद से राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव बढ़ा था। लेकिन, उप राष्ट्रपति के अपमान का मामला गरमा गया है। जाट वोट बैंक सीधे तौर पर बिरादरी के आत्मसम्मान को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भाजपा यूपी में मिशन 80 को सफल बनाने के लिए विपक्ष के द्वारा की गई हर गलती को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। जाट वोट बैंक को साधने के लिए पहले मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की जयंती कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया है। मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 23 दिसंबर को पूर्व पीएम की जयंती के मौके पर इसका अनावरण होगा। इस कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से मौजूद होंगे। इससे पहले जाट आत्मसम्मान का मुद्दा गरमाने लगा है। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान से सबसे ज्यादा नुकसान रालोद पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को हो सकता है। क्योंकि मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों के बाद से जाट वोट बैंक अलग हो गया। जाट– मुस्लिम गठजोड़ हमेशा राष्ट्रीय लोक दल को फायदे में रखता था। किसान आंदोलन के बाद से जाट वोक बैंक का एक वर्ग रालोद के साथ जाता दिखा। लेकिन, अब जगदीप धनखड़ के अपमान का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। जयंत भी विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का हिस्सा हैं। ऐसे में वे भी इस मामले में कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) से दूरी बनाने वाले दलों के बारे में अनावश्यक टीकाकृटिप्पणी नहीं करने की सलाह देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भविष्य में कब, किसको, किसकी जरूरत पड़ जाए, यह कहा नहीं जा सकता। मायावती ने यहां एक बयान में किसी का नाम लिये बगैर कहा, श्रविपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं उनके बारे में किसी का भी फिजूल की टीकाकृ टिप्पणी करना उचित नहीं है।

एंटी करप्शन की टीम ने एआरएम को घूस लेते पकड़ा

बांदा। एंटी करप्शन की टीम ने बांदा रोडवेज के एआरएम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एआरएम संविदा चालक को सेवा समाप्त किए जाने की धमकी देकर 11 हजार की रिश्वत ले रहे थे। एंटी करप्शन की टीम एआरएम को कोतवाली ले गई और पूछताछ की। इसके बाद मेडिकल कराकर कोतवाली के लॉकअप में बंद कर दिया। रोडवेज में सविंदा ड्राइवर नवल किशोर बांदा से लखनऊ बस चलाता है। बांदा रोडवेज एआरएम लक्ष्मण सिंह संविदा ड्राइवर को संविदा समाप्त करने की धमकी देकर आए दिन रिश्वत मांगता था। जिससे परेशान होकर नवल ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन में कर दी। जिसके बाद दोपहर को आठ सदस्यीय टीम ने नवल से 11 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एआरएम को रंगे हाथों पकड़ लिया। संविदा समाप्त परिचालक महेंद्र ने बताया कि बबेरू निवासी ड्राइवर वेदप्रकाश ने एआरएम से परेशान होकर प्रयागराज में तीन माह पहले आत्महत्या कर ली थी। घरवालों ने एआरएम लक्ष्मण सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखाया था जिस पर जांच विचाराधीन है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों ने एआरएम के खिलाफ कई हफ्तों तक आंदोलन चलाया। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, लेकिन अपनी पहुंच के बल पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इसके कई वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इससे नाराज होकर एआरएम ने शिकायत करने वाले तीन दर्जन से अधिक संविदा कर्मियों की संविदा भी समाप्त कर दी थी।

कांग्रेस नेताओं को भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण

लखनऊ,(यूएनएस)। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट ने कांग्रेस नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण भेजा है। पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण भेजने की प्रक्रिया जारी है और आने वाले दिनों में और भी विपक्षी नेताओं को निमंत्रण मिलेगा।22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर चौधरी को आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी और खड़गे को राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल ने आमंत्रित किया था, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। उद्घाटन समारोह में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों का नाम आमंत्रित लोगों की सूची में नहीं है। कई मुख्यमंत्री राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं, जिन्हे निमंत्रण है।काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुख ,धार्मिक, संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधि, आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी, योग गुरु बाबा रामदेव, अभिनेता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत, इसरो निदेशक नीलेश देसाई जैसे उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है।विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित किया, जो 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे थे। दोनों ने कहा कि अगर स्वास्थ्य अनुमति देगा तो समारोह में शामिल होने का हरसंभव प्रयास करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं और एमएम जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। प्रतिष्ठा समारोह के बाद 24 जनवरी से 48 दिनों के लिए मंडल पूजा होगी और 23 जनवरी से रामलला के दर्शन जनता के लिए खुले रहेंगे।

एमडीआर टीबी पर जेएन मेडिकल कालिज में प्रशिक्षण कार्यक्रम

अलीगढ़, (यूएनएस)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग द्वारा एनटीईपी के तहत डीआर टीबी सेंटर में काम करने वाले रेजीडेंट्स और कर्मचारियों के लिए ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिसः हालिया अपडेट पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद शमीम ने एमडीआर तपेदिक के विभिन्न कारणों, इसके निदान के विभिन्न तरीकों और एमडीआर तपेदिक उपचार में हाल की प्रगति की बेहतर समझ के लिए प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया। एनटीईपी के नोडल अधिकारी डॉ. नफीस अहमद खान ने एमडीआर के बोझ और इसके कारणों को समझने के महत्व के बारे में बात की। डब्ल्यूएचओ सलाहकार डॉ. उमर अकील ने तपेदिक रोगियों के लिए सरकारी सहायता और दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए विभिन्न उपचार व्यवस्था और नवीनतम उपचार अपडेट के बारे में बताया। डॉ. शहजाद अनवर ने एमडीआर क्षय रोग की रोकथाम में जन जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण में डॉ. इमराना मसूद सहायक प्रोफेसर, डॉ. इमरान सिद्दीकी, उप–प्राध्यापक डीटीओ, श्वसन औषधि विभाग के रेजीडेंट्स और डीआरटीबी कार्यचारियों ने भाग लिया।

कूड़े में तड़पती मिली नवजात बच्ची,कुत्ते नोच रहे थे, महिलाओं ने छुड़ाया, अस्पताल में तोड़ा दम

उरई/जालौन। जालौन में मानवता को शर्मसार और दिल झझकोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी दो दिन की मासूम बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। इस बारे में तब जानकारी मिली

जब कुत्ते उसे मासूम बच्ची को नोच रहे थे। इस घटना को आसपास की महिलाओं ने देखा तत्काल मौके पर पहुंची, जिन्होंने कुत्ते से छुड़ाकर मासूम बच्ची को महिला जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देख उसको सीआरपी देकर बचाने का प्रयास किया। मगर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के लहरियापुरवा इलाके का है। जहां एक मासूम बच्ची पड़ी हुई थी, जिसको लेकर कुत्ते आपस में लड़कर उसे नोच रहे थे, जिसे देख स्थानीय महिलाये पहुंची, जहां उन्होंने मासूम को देखा तत्काल कुत्तों से उस मासूम बच्ची को छुड़ाकर इलाज के लिए महिला अस्पताल लेकर पहुंची। जहां महिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा उसको देखते हुए सीआरपी देकर बचाने का प्रयास किया। मगर बच्चे के सिर में घाव होने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना तत्काल महिला अस्पताल के चिकित्सकों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने 2 दिन के मासूम बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। इस घटना के बारे में बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची मालती वर्मा ने बताया कि वह अपने घर के बाहर कुत्तों को लड़ते हुए देख रही थी जो किसी मासूम बच्ची को ले जा रहे थे, उन्होंने तत्काल मासूम बच्ची को उन कुत्तों से छुड़ाया और महिला अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले के बारे में महिला अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल कद्दूस ने बताया कि महिलाओं द्वारा एक मासूम बच्ची लाया गया था जिसका शरीर ठंडा था। उसे सीआरपी देने के बाद बचाने का प्रयास किया, मगर उसकी मौत हो गई। उसके सिर पर कुत्ते द्वारा नोचने के निशान थे। महिलाओं द्वारा बताया गया कि उस मासूम बच्ची को कुत्ते ले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि मासूम एक या दो दिन की है।

सैनिक स्विमिंग प्रबंधन की लापरवाही से हुई छात्र की मौत,

वार्डन, स्वीमिंग कोच समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

लखनऊ। लखनऊ में सैनिक स्कूल में 8 सितंबर 2023 को संदिग्ध हालात में हुई 11वीं के छात्र ओम बुधौलिया की मौत मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दर्ज गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूरे घटना में स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदारों की लापरवाही से छात्र की मौत हुई। इसके चलते स्कूल के वार्डन, स्विमिंग कोच और लाइफ गार्ड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मूलरुप से उरई निवासी सीआरपीएफ में एएसआई मनोज कुमार का बेटा ओम बुधौलिया सैनिक स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। आठ सितंबर की शाम ओम का शव स्कूल परिसर में बने स्वीमिंग पूल में उतराता मिला था। 16 सितंबर को मनोज ने सरोजनीनगर थाने में स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन, लाइफ गार्ड, शिक्षक व कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कराया था। वहीं, मंडलायुक्त ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर शैलेंद्र गिरि ने बताया, केस की विवेचना में गैर इरातदत हत्या या हत्या को लेकर कोई सुबूत नहीं मिले। छात्र की मौत लापरवाही की वजह से हुई। जिसमें वार्डन राजीव वर्मा, कोच सत्या चौहान और लाइफ गार्ड हिमांशु शर्मा के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि छात्र को लाइफ जैकेट नहीं दिया गया था। छात्र स्वीमिंग सीख रहा था। इसके बावजूद कोच, लाइफ गार्ड आदि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं, छात्रों की संख्या के हिसाब से ट्रेनर कम थे। ओम के जूते, चश्मा, कपड़े आदि चेंजिंग रूम में ही रखे रहे थे। किसी ने नहीं देखा और सब हॉस्टल लौट गए। जिसके चलते ओम का शव कई घंटे पूल में ही पड़ा रहा।

जॉब फेयर...350 सिलेक्ट हुए,18 कंपनियां फेयर में शामिल हुई

अलीगढ़। जनपद में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए IIMT में जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जिला सेवायोजन कार्यालय के सहयोग से आईआईएमटी कैंपस में जॉब फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। जिसके बाद मौके पर इंटरव्यू के जरिए उनका चयन किया गया। जॉब फेयर की उद्घाटन IIMT के अध्यक्ष पंकज महलवार और सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी मनोज कुमार भारती ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर किया। जिसके बाद युवाओं के इंटरव्यू का कार्यक्रम शुरू हुआ। चयनित युवाओं को कंपनियों ने अगले चरण के लिए तत्काल लेटर भी दिए गए। आईआईएमटी कैंपस में लगे रोजगार मेले में 530 से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और कंपनियों ने उसका इंटरव्यू लिया। साक्षात्कार के आधार पर प्रारंभिक चरण में 350 युवाओं का चयन किया गया है। जिन्हें अगले चरण के लिए आमंत्रित किया गया है। युवाओं का इंटरव्यू लेने के लिए रोजगार मेले में 18 कंपनियां और उनके अधिकारी शामिल हुए। इसमें अलीगढ़ के साथ ही दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ समेत विभिन्न जिलों से कंपनियां रोजगार मेले में आई। जिसके बाद सभी चयनित युवाओं को आईआईएमटी के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। युवाओं का चयन करने के लिए 18 कंपनियां शामिल हुई। इसमें इनक्यूबेशन सेंटर, क्रैक ईडी कंपनी गुड़गांव, तालानगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन एवं रोजगार प्रोत्साहन मार्गदर्शन केंद्र अलीगढ़, एडमेंट नोएडा, आईसीएमएस ग्रुप, एचडीएफसी इंश्योरेंस, पावना जाड़ी, एके मैनपॉवर, हीरो ग्रुप हरिद्वार, साधु फोर्जिंग गियर डिवीजन फरीदाबाद समेत कई अन्य कंपनियां शामिल हुई। इस दौरान मेला प्रभारी देवेंद्र कुमार, प्रिंसिपल शंभू केएन सिंह रावत, राजेश कुमार, सुशील कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, सोहन सिंह वरिष्ठ सहायक, हर्षित शर्मा तथा प्रतीक कुमार समेत विभिन्न लोग शामिल रहे।

सभी साहबा सितारों की तरह सम्मानित मार्गदर्शक हैं : अफाक

लखनऊ,(यूएनएस)। राष्ट्रीय सामाजिक कार्य कर्ता संगठन के संयोजक मोहम्मद अफाक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अलहम्दुलिल्लाह अहल–ए–सुन्नत वलजमात का सर्वसम्मत विश्वास है कि सभी साहबा राजी० सम्मानित मार्गदर्शक की तरह सितारे के हें। जो लोग बनू उमैया के कबीले से ताल्लुक रखने वाले हजरत अमीर मुआविया राजी० को कोस रहे हैं और उन्हें बदनाम कर रहे हैं, वे अहलेबैत के नाम पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ओलेमा को ध्यान देने की सख्त जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में खुलेफाये राशिदीन पर भी उंगलियां उठायेंगे. उन्होंने कहा कि आज देश और विश्व व्यवस्था की परिस्थितियों को देखते हुए हमें अराजकता से बचने की सख्त जरूरत है। छोटे मदरसों को इस समय जलसा जुलूस कर ने से बचना चाहिए और जो नात गायक इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें केवल अल्लाह की एकता और मुस्तफा सल० की नात खानी ही की जानी चाहिए। यह सलाह दी जानी चाहिए कि आज के पीर व मुरीद पर कसीदा पढ़ने से बचें और उपदेशों से भरी सभा में बे धर्मों को खारिज करने के अलावा किसी के खिलाफ बोलने से बचें। और बानु उमय्या से ताल्लुक रखने वाले कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया राजी० के बारे में केवल सभा में चर्चा की जानी चाहिए। अंत में, मुहम्मद अफाक ने कहा कि मुझे दृढ़ता से लगता है कि मुस्लिम युवाओं को हमारे आपसी मतभेदों से नफरत करके बुरे धर्मों की कतार में शामिल नहीं होना चाहिए। अन्यथा इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। बजाय इसके कि हम इस पर लाखों रुपये खर्च करें। मतभेदों के नाम पर होने वाली बैठकों में हमें मुस्लिम उम्माह की बातें सिखानी और सिखानी चाहिए।

रात की अंधेरे में सड़क पर उतरे डीएम,अधीनस्थों को अलाव जलवाने के लिए निर्देश

उरई/जालौन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुये असहायों और जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडेय ने बुधवार रात आराम करने की बजाय उरई शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर भ्रमण किया और अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज सहित अन्य इलाकों में जाकर जरूरतमंद और असहाय लोगों को घूम–घूम कर अपने हाथों से 50 से अधिक कंबल का वितरण किया। इस दौरान कंबल प्राप्त करने के बाद असहाय और जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं सड़क किनारे पटरियों पर सोने वाले लोगों को डीएम ने रैन बसेरे और शेल्टर होम में शरण दिलाई, साथ अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए जो खुले आसमान के नीचे रात काटने वाले लोग है, उन्हे रैन बसेरा व शेल्टर होम में आश्रय दिलाया जाए। बुधवार रात जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडेय ने शहर के अलग–अलग इलाकों में जाकर भ्रमण किया, उन्होंने रैन बसेरा व आश्रय स्थलों का भी जाकर निरीक्षण किया, साथ ही सर्दी में बाहर से आने वाले लोगों को रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही रैन बसेरे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास अलाव की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए, साथ ही ठंड से बचाव के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी ली, इस दौरान डीएम ने रैन बसेरे और शेल्टर होम में ठहरे हुए लोगों से बात कर उनका हाल पूंछा और व्यवस्था के बारे में बात की। डीएम राजेश कुमार पांडेय ने उरई रेलवे स्टेशन जाकर भ्रमण किया, जिन्होंने जरूरत मंद लोगों को कंबल का वितरण किया, साथ ही रैन बसरों में जाकर बाहर से आने–जाने वाले लोगों को बेड खाली होने पर समुचित व्यवस्था और क्षमता के अनुसार सभी रैन बसेरों में लोगों को रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिए कि बाहर खुले में रात गुजारने वाले लोगों को रैन बसेरा व शेल्टर होम में शरण दिलाई जाये और उनके लिए उचित व्यवस्था की जाये। डीएम ने रोडवेज बस स्टैंड, स्टेशन, जिला अस्पताल, पटरियों पर सोने वाले और मेडिकल कॉलेज में जाकर 50 से अधिक लोगों को कंबल का वितरण किया। इस दौरान डीएम राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि उन्होंने सभी तहसील क्षेत्र और नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने–अपने क्षेत्र में रात्रि में भ्रमण करते हुए जरूरतमंदों को कंबल वितरित करें, साथ ही बनाए गए रैन बसेरा और शेल्टर होम का भी निरीक्षण करे, जिससे भीषण शीत लहर में लोगों को ठंड से बचाया जा सके, इसके अलावा हर इलाके में अलाव जलवाने की भी व्यवस्था की जाये, इस दौरान एडीएम नमामि गंगे विशाल यादव, नगर मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार, तहसीलदार कुमार भूपेंद्र सिंह, अपर सूचना अधिकारी पंकज तिवारी, ओएसडी अनूप श्रीवास्तव मौजूद रहे।

राजनीति में कब, किसको, किसकी जरूरत पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) से दूरी बनाने वाले दलों के बारे में अनावश्यक टीकाकृ

टिप्पणी नहीं करने की सलाह देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भविष्य में कब, किसको, किसकी जरूरत पड़ जाए, यह कहा नहीं जा सकता। मायावती ने यहां एक बयान में किसी का नाम लिये बगैर कहा, विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं उनके बारे में किसी का भी फिजूल की टीकाकृटिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वह इससे बचें, क्योंकि भविष्य में, देश में, जनहित में कब किसको, किस की जरूरत पड़ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बसपा प्रमुख ने कहा, टीकाकृटिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े यह ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खासतौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने से साफ इंकार करते हुए अपने बलबूते अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मायावती ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में निलंबित विपक्षी सांसदों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का वीडियो बनाने को श्अशोभनीयश करार देते हुए कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव और टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी की है।उन्होंने हाल ही में लोकसभा की सुरक्षा में चूक को भी गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आरोपकृप्रत्यारोप के बजाय सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मायावती ने कहा कि इस मामले के जो भी दोषी और षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना बेहद जरूरी है। बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष दल है और उसे अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अगले महीने होने जा रहे उद्घाटन पर कोई भी ऐतराज नहीं है । उन्होंने साथ ही कहा कि बसपा को अयोध्या में अदालत के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर निर्मित होने वाली मस्जिद के उद्घाटन पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने किसी का नाम लिये बगैर कहा, श्लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वह अत्यंत दुखद और चिंतनीय भी है। मायावती ने कहा कि ऐसी चीजों से देश कमजोर ही होगा और इससे लोगों में आपसी नफरत पैदा होती है जो कतई उचित नहीं है।

बच्चों को संस्कारित बनाने में परिवार की भूमिका अहम : आचार्य गोविंद मिश्रा

लखनऊ। हमें अपने बच्चों का नाम बहुत ही सोंच विचार कर रखना चाहिये क्योंकि नाम की महिमा होती है। कुल गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों का नामकरण करने राजा दशरथ के महल में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उनके बड़े पुत्र का नाम राम रखा। बच्चे के बारे में जब बताया तो अयोध्या में उनकी जय–जयकार होने लगी। पंडाल में बैठे भक्तजन भी इस प्रसंग को सुन उत्साहित होकर जयकारे लगाने लगे। विश्वनाथ मन्दिर के 32वें स्थापना दिवस के मौके पर श्रीरामलीला पार्क सेक्टर–ष्ए० सीतापुर रोड योजना कालोनी में चल रहे मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम कथा के चौथे दिन गुरुवार को कथा व्यास आचार्य गोविंद मिश्रा ने नामकरण, अहिल्या उद्धार, नगर दर्शन का प्रसंग सुनाया। नामकरण का प्रसंग सुनाते हुये उन्होंने बताया कि सभी को सुख देने वाले, सभी को भव से पार कराकर विश्राम देने वाले उनका नाम राम है। उनके नाम के स्मरण मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान ने जन्म ही संसार में आकर लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए लिया था। कथाव्यास ने कहाकि जिस भगवान की गोद में ब्रह्माण्ड खेलता है, वह भगवान बालरूप में माता कौशल्या की गोद में खेलते हैं। जिनकी गोद में दुनियाँ हँसती रोती है वे माता कौशल्या की गोद में कभी रोते हैं तो कभी हंसते है। भगवान की बाललीला अदभुत और मनमोहक है।

आचार्य गोविंद मिश्रा ने कहाकि आज भारत का बचपन नष्ट हो रहा है। बचपन नष्ट करने वाले कोई और नहीं, बल्कि उनके परिवार ही हैं। यदि बचा सके तो आज बचपन बचाएँ। बच्चे अपने परिवार की पाठशाला में ही सर्वप्रथम सीखतें हैं। हमारा पारिवारिक जीवन जैसा होगा, भावी पीढ़ी भी वैसी ही होगी। परिवार में जैसे संस्कार होगें, वैसा ही संस्कार बालक सीखता है।

प्रोफेसर आरिफ नजीर नये ईसी सदस्य नियुक्त

अलीगढ़, (यूएनएस)। प्रोफेसर आरिफ नजीर, डीन, कला संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को डीन पद के वरिष्ठता के क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बन गये बन गये है। उनका कार्यकाल 23 दिसंबर से संबंधित संकाय के डीन पद पर बने रहने तक होगा प्रोफेसर आरिफ नजीर अप्रैल 1983 से एक संकाय सदस्य के रूप में एएमयू से जुड़े हुए हैं। उन्हें 1991 में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया और 2002 में एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा दो डी. लिट डिग्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें यूजीसी रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। था। प्रोफेसर नजीर 10 पुस्तकों के लेखक और उर्दू से हिंदी में एक पुस्तक के सह–अनुवादक हैं। उनके विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 101 से अधिक शोध पत्र और लगभग 17 लेख प्रकाशित हुए हैं प्रोफेसर नजीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें नटाली पुरस्कार (2005–6), प्रवासी भारतीय महाकवि हरि शंकर आदेश साहित्य सिंधु सम्मान (2011), वार्षिक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में नागरी लिपि परिषद पुरस्कार, अनुसंधान समूह शामिल हैं। छह बार यानी 1987, 88, 92, 94, 99 और 2000 में अब्दुल रहीम खानखाना सम्मान (2000), हिंदी रत्न सम्मान (2001), वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान (2010), गोस्वामी तुलसीदास समर्पण सम्मान, विश्व विद्या सितारा सम्मान, डॉ. .महेंद्र सागर प्रचंडीय स्मृति साहित्य वारिधि सम्मान, और विश्व हिंदी सेवी सम्मान शामिल है।

नैनोटेक्नोलॉजी रुझानों पर वेबिनार का आयोजन

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंटरडिसिप्लिनरी नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर (आईएनसी) ने 'नैनोटेक्नोलॉजी में रुझान' विषय पर वेबिनार की श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया। प्रोफेसर अबसार अहमद ने श्बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए जैव–नैनो–कंपोजिट के डिजाइन और अनुप्रयोग' पर बोलते हुए वैज्ञानिक समुदाय के लिए नैनो–कंपोजिट के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब नैनोकम्पोजिट का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के साथ किया जा रहा है। वर्जीनिया टेक, यूएसए के प्रोफेसर अजहर अली ने नैनोमटेरियल के उन्नत निर्माण में उन्नत तकनीकों और बायोसेंसिंग प्रौद्योगिकी में उनके अनुप्रयोग पर चर्चा की।

नोट्रे डेम विश्वविद्यालय, यूएसए के प्रोफेसर सत्य ज्योति सेनापति ने बायोसेंसिंग प्लेटफार्मों में नैनोमटेरियल्स के एकीकरण और स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण निगरानी के लिए उनके निहितार्थ पर प्रकाश डाला। डीटीयू, नई दिल्ली के प्रोफेसर बीडी मल्होत्रा ने अपने शोध पर चर्चा करते हुए कैंसर बायोमार्कर का पता लगाने के लिए पेपर सेंसर की उपयोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने औद्योगिक अनुप्रयोग और बाजार के रुझान के बारे में बात करते हुए नैनोमटेरियल आधारित बायोसेंसर में शामिल कंपनियों के साथ सहयोग पर जोर दिया।

प्रोफेसर एचबी बोहिदार ने 'मल्टीफंक्शनल नैनोकम्पोजिट हाइड्रोजेल' पर बात की, जो वास्तव में नैनोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंस का एकीकरण है, जिसने स्वास्थ्य देखभाल और उपचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एएमयू के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय के डीन प्रोफेसर मुहम्मद अल्तमिश सिद्दीकी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में नैनोमटेरियल्स के अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला। आईआईसीटी, हैदराबाद के डॉ. चितरंजन पात्रा ने खनिज नैनोकणों के महत्व पर चर्चा की जो क्षतिग्रस्त ऊतकों में परिसंचरण को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोना, चांदी और अन्य धातु के नैनोकणों में अद्वितीय गुण होते हैं जो जैविक प्रतिक्रियाओं में उपयोगी होते हैं और ऊतक पुनर्जनन को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। जामिया हमदर्द, नई दिल्ली के प्रोफेसर शमीम अली ने लक्षित दवा वितरण में हर्बल नैनोमेडिसिन के संभावित उपयोग पर प्रकाश डाला। जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के प्रोफेसर शरीफ अहमद ने हाइड्रोजेल की क्षमता और उपयोगिता के बारे में बात की और एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां व्यक्तिगत चिकित्सा और ऊतक पुनर्जनन अधिक सफल होगा। जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एएमयू के प्रिंसिपल प्रोफेसर एमएम सुफियान बेग ने वेबिनार को छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी बताया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से लाभ उठाने का अवसर मिलता है। आईएनसी निदेशक डॉ. मुहम्मद अजहर अजीज ने आमंत्रित वक्ताओं, अतिथियों और प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने छात्रों को अनुसंधान और नवाचार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसे वेबिनार और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मौखिक प्रस्तुति में इंटरडिसिप्लिनरी नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर के शोध विद्वान आजम रजा को सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति पुरस्कार से नवाजा गया। विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. सालेहा नसीम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। यह कार्यक्रम हाईब्रिड मोड में आयोजित किया गया।

यूपी पुलिस ने शुरू किया पब्लिक ग्रीवेंस रिव्यू पोर्टल, लोगों की शिकायत पर अधिकारी की होगी सीधी नजर

लखनऊ,(यूएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जनता की समस्याओं के समय से निस्तारण के लिए पब्लिक ग्रीवेंस रिव्यू पोर्टल की शुरू किया है। डीजीपी विजय कुमार के बताया कि इस पोर्टल के जरिए एक तरफ जहां गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी लोगों की शिकायत संबंधी मामलों का सुपरविजन भी कर सकेंगे। इस पोर्टल से शिकायतकर्ता की पूरी जानकारी सिर्फ एक क्लिक से मिल जाएगी। डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि जनता की समस्याओं को समयबद्ध, त्वरित निस्तारण और मॉनिटरिंग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में पब्लिक ग्रीवेंस रिव्यू पोर्टल शुरू किया गया है। इसके तहत मैन्युअली प्राप्त प्रार्थना पत्रों को डिजिटाइज्ड कर, प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इससे जहां एक ओर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी वही दूसरी ओर पुलिस आला अधिकारी प्रभावी अनुश्रवण भी कर सकेगे, क्योंकि अफसर आसानी से शिकायतों को एक क्लिक पर देख सकेंगे। प्रदेश के सभी जिलों या थानों के प्रार्थना पत्रों की अद्यतन स्थिति समेकित डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। इस डैशबोर्ड को डीजीपी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक देख सकेंगे। इस पोर्टल के विकसित होने से थाने पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का एक इलेक्ट्रानिक डाटाबेस बनेगा। विभिन्न स्तर के अधिकारियों के सुपरविजन से उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा।

जलकल जीएम के खिलाफ पार्षद धरने पर बैठे

लखनऊ। लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी के बैठक में जीएम जलकल के खिलाफ पार्षद समेत मेयर ने नाराजगी दिखाई। मेयर की आदेश का अवहेलना करने के आरोप में पार्षद जीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षद रंजीत ने उनके ऊपर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। यहां तक की कार्यकारिणी सदस्यों के सवालों से जलकल विभाग के महाप्रबंधक मनोज आर्या करीब पांच घंटे तक घिरे रहे। लगातार हंगामा देख जीएम बैठक ही छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है और वह बैठक छोड़कर चले गए। ऐसे में। जीएम के इस रैवये को लेकर सभी सदस्य धरने पर बैठ गए। कार्यकारिणी में निंदा प्रस्ताव लाया गया और आगामी चुनाव को देखते हुए महाप्रबंधक को हटाए जाने के लिए कार्यकारिणी की मंशा से शासन को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि दो दिसंबर को वह बालागंज वाटर वर्क्स का निरीक्षण करने गई थी। यहां पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती में अनियमितता मिली थी। इसके बाद जीएम को अजय सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिया गया। मगर अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर मेयर ने उनके आदेश का अनुपालन न करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भी जीएम को 13 दिसंबर को पत्र लिखकर कार्रवाई न करने की वजह पूछी। इस पर जीएम ने हाल ही में नियुक्ति, बैठकों व महत्वपूर्ण काम न होने की वजह बताया। भाजपा के 10 व सपा के दो पार्षदों ने जीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्हें पार्षदों के साथ अध्यक्ष ने भी खरीखोटी सुनाई। भविष्य के लिए हिदायत भी दी। इस पर जीएम ने माफी मांगने की बजाय कहा उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्हें ही काफी देर से टारगेट किया जा रहा है। इस पर कार्यकारिणी का माहौल और गर्म हो गया। मेयर का अपमान होने पर पार्षदों का आक्रोश फूट पड़ा। राजकुमार हाल में बैठक के दौरान धरने पर बैठ गए। गोमतीनगर रेलवे स्टेशन को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से करने की भी मंजूरी दे दी गई है। सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी के प्रस्ताव को पास करने के बाद अब इसे शासन भेजा जाएगा। इसके अलावा हुसैनगंज चौराहे का नाम महाराणा प्रताप चौराहा किया गया है। नक्खास बाजार के पास महिला शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव पास कर दिया गया।

फरार अमरमणि त्रिपाठी...मामले की सुनवाई टली,अब 10 जनवरी को होगी किडनैपिंग केस में हियरिंग

बस्ती। जिले के बहुचर्चित व्यापारी धर्मराज के पुत्र राहुल अपहरण कांड में फरार चल रहे अमरमणि त्रिपाठी की आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई। सुनवाई की अगली तिथि 10 जनवरी तय की गई है। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा। अपहरण मामलें में वांछित चल रहे आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के मामले में दो दिसंबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम,विशेष न्यायाधीश (एमपी–एमएलए कोर्ट) प्रमोद कुमार गिरि ने पुलिस को नई टीम गठित करने के आदेश दिए। आदेश में कोर्ट ने कहा कि मामले में अमरमणि के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके बाद 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख पर रिपोर्ट करें। इससे पहले न्यायालय के आदेश पर पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के लिए एसपी स्तर से पुलिस टीम का गठन किया गया था, लेकिन टीम आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए कोतवाल को तलब कर लिया था। दो दिसंबर को दूसरी टीम का गठन करके कुर्की कर 20 दिसंबर तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर चले जाने के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो पाई, अगली तिथि 10 जनवरी निर्धारित की गई है। न्यायालय के आदेश के बाद एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक कृपाशंकर मौर्य, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संजय कुमार, एसओ महिला थाना निधि यादव, एसओजी व स्वॉट प्रभारी और चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस को टीम में शामिल किया गया है। टीम के पर्यवेक्षण का जिम्मा सीओ सिटी विनय चौहान को सौंपा गया है।

संसद में आवाज उठाने वाले सस्पेंड और सड़क पर आवाज उठाने वालों को भेजा जा रहा जेल : राकेश टिकैत

बहराइच, (यूएनएस)। श्रावस्ती दौरे पर जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत का बहराइच में स्वागत हुआ। डीएम ऑफिस के बाहर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किसान नेता राकेश टिकैत का भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में उन्होंने कहा कि आखिर आरोपियों के पास किसने बनवाए। कोई तो है जो उन्हें अंदर लेकर गया। हमारी एजेंसिया इतनी कमजोर नहीं हैं। हो सकता है यह जान बुझ भी किया गया, हो सकता है और यह सरकार की जिम्मेदारी है और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। संसद से सांसदों को सस्पेंड किए जाने के मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा है, जो आवाज उठाएगा वह सस्पेंड होगा। आम आदमी आवाज उठाएगा जेल जाएगा। सांसद आवाज उठाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। यह देश गुलामी की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आम लोगों की नहीं, बल्कि व्यापारियों की सरकार है। जो आवाज उठाएगा वह जेल में जाएगा या मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और वहां का हर्षा जंगल अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है जंगल काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आदिवासी हैं जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं। उन्हें नक्सलवादी बताकर जेल में डाला जा रहा है। कल भी वहां लाठीचार्ज हुआ और लोगों को जेल में डाला गया। EVM के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीते का सर्टिफिकेट लेकर गया। डेढ़ सौ से अधिक फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ना कोई कोर्ट गया ना कोई इलेक्शन कमीशन गया। हारा हुआ कैंडिडेट भी भाजपा मुख्यालय गया। इलेक्शन कमीशन व कोर्ट नहीं गया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से नहीं, बल्कि बिना ईवीएम के चुनाव होना चाहिए। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों का डिजिटल भुगतान होना चाहिए, जब देश डिजिटल की ओर जा रहा है, तो फिर किसानों का भी भुगतान डिजिटल रूप से होना चाहिए, लेकिन देश पर व्यापारी हावी है।

डीएम ने की विकास के कामों की समीक्षा,डीआईओएस और ईओ नानपारा की सैलरी रोकने के निर्देश

बहराइच। डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नानपारा की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होनें विभिन्न विभागों की मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर रैंकिंग की समीक्षा के दौरान ''बी,सी,डी,ई'' श्रेणी के रैंकिंग वाले विभागों पर कड़ी अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सम्बन्धित विभाग विशेष प्रयास कर महीने के अन्त तक रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाए, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए वेतन बाधित करने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर विभागीय प्रगति की फीडिंग जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं अपनी देख–रेख में कराए। बैठक के दौरान पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, समाज कल्याण, लोक निर्माण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पशु पालन इत्यादि विभागों के प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। 50 लाख से अधिक एवं 50 लाख से कम लागत की निर्माण परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश की जिन परियोजनाओं की भूमि उपलब्ध हो गयी है। वे निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। यदि कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू नहीं कराती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बंध में प्रशासकीय विभागों को भी निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से समन्वय कर परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराएं, ताकि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके। प्रशासकीय विभाग अपनी विभाग की निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराए जाने के लिए समय–समय पर निर्माण परियोजनाओं का स्वयं निरीक्षण करते रहे। जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, उसे अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को हैंडओवर करा दिया जाए, ताकि परियोजनाओं को जन उपयोग में लाया जा सके। इस अवसर पर सीडीओ रम्या आर और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

संगमम-2 के गोदावरी ग्रुप ने किया विश्वनाथ मंदिर में दर्शन,टेंपल में फूलों से स्वागत

वाराणसी। काशी–तमिल संगमम का तीसरा जत्था गोदावरी ग्रुप आज वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी मंदिर और सारनाथ का भ्रमण किया। इससे पहले हनुमान घाट पर गंगा स्नान कर कवि भारथियार के घर भी गए थे। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और अधिकारियों ने उन पर पुष्पवर्षा की। मंदिर कॉरिडोर के शंकराचार्य चौक से केवल महादेव की गूंज ही सुनाई दे रही थी। यहां पर शास्त्रीय नृत्य करके पारंपरिक तौर पर प्रोफेशनल्स ग्रुप का वेलकम किया गया। डेलीगेशन में आए 200 से ज्यादा लोगों ने इस अंदाज में स्वागत देख हर–हर महादेव का जयघोष किया। तमिल डेलीगेट्स में सभी 205 लोग प्रोफेशनल्स कटेगरी के हैं। यानी कि नौकरीपेशा से लेकर छोटे उद्यमी इसमें शामिल हैं। दर्शन के बाद प्रोफेशलन्स का ग्रुप एक साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र में भोजन किया। तमिल डेलीगेट्स का यह जत्था बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और कॉरिडोर भ्रमण के बाद विशालाक्षी मंदिर भी गया। यहां पर विधि–विधान से पूजा की गई। आज शाम को ये दल सारनाथ भ्रमण किया। यहां पर गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली और म्यूजियम के साथ ही धमेख स्तूप को भी बड़े ध्यान से देखा। सभी डेलीगेट्स ने अशोक स्तंभ, बुद्ध प्रतिमा और स्तूप के आगे फोटो खिचवाई। कल एकेडमिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी होगी।

आठ सूत्री मांग को लेकर एमआरओ का कार्य बहिष्कार

बस्ती। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने आठ सूत्री मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार किया। जीआईसी में सभी सदस्य एकत्रित हुए। इसके बाद मांगों पर चर्चा की। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बस्ती केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया।

सचिव रंजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार से संगठन बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 की रक्षा करने, बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाए जाने, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने तथा संस्थान और उनके काम का अधिकार सुनिश्चित करने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करने और जीएसटी हटाने, डेटा गोपनीयता को सुरक्षित रखने की मांग उठाई। इसके अलावा संगठन ने बिक्री संबंधी शोषण और उत्पीड़न बंद करने, ट्रैकिंग और सर्विलांस के माध्यम से गोपनीयता में कोई घुसपैठ नहीं करने, कार्यस्थलों में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। इस मौके पर शोएब रहमान, उपाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, मोहित गुप्ता, उपसचिव सोनू , अमित पांडेय आदि मौजूद रहे।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com

R.N.I.- UPHIN/2012/45127

नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।